SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

ई–एनएएम के माध्यम से किसानों को होने वाले लाभों का विश्लेषण

गौतम कुमार, शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग
राँची विश्वविद्यालय, राँची, झारखंड़, भारत
बिद्यानंद चौधरी, पी–एचडी, शोध निर्देशक, अर्थशास्त्र विभाग
जे.एन. कॉलेज, धुर्वा (आर.यू.), राँची, झारखंड़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
गौतम कुमार, शोधार्थी
बिद्यानंद चौधरी, पी–एचडी., शोध निर्देशक
E-mail : gautamk881@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 16/08/2025
Revised on : 14/10/2025
Accepted on : 23/10/2025
Overall Similarity : 00% on 15/10/2025

शोध सार

यह अध्ययन किसानों के लिए ई–एनएएम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) के लाभों का आकलन करता है, जिसने 2016 से पारंपरिक कृषि विपणन को पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और तकनीकी आधारित प्रणाली में बदलने में भूमिका निभाई है। झारखंड के 153 किसानों पर आधारित सर्वेक्षण में 57.1 प्रतिशत किसान ई–एनएएम से परिचित पाए गए। अधिकांश किसान मूल्य निर्धारण व गुणवत्ता आश्वासन के लिए पहुंच को आवश्यक मानते हैं, जबकि ई–नीलामी और डिजिटल तौल को अधिकतर ने पारदर्शी व सटीक माना। हालांकि, नकद भुगतान की प्राथमिकता और डिजिटल भुगतान पर भरोसे की कमी जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। आधे से अधिक किसानों ने पारंपरिक बाजारों की तुलना में बेहतर मूल्य, अधिक खरीदारों तक पहुँच और वित्तीय स्थिति में सुधार की पुष्टि की। अध्ययन में ई–एनएएम के विस्तार, गुणवत्ता परीक्षण व तौल प्रणाली को सुदृढ़ करने, एफपीओ को प्रोत्साहन देने और जागरूकता कार्यक्रमों की सिफारिश की गई है ताकि इसका व्यापक लाभ किसानों तक पहुँच सके।

मुख्य शब्द

ई–एनएएम, कृषि विपणन, पारंपरिक बाजारों, झारखंड, एफपीओ.

परिचय

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है और अधिकांश भारतीय परिवारों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण पेशा है। इसी को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने पूरे देश में एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार व्यवस्था की शुरुआत की। 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कृषि बाजार (नेशनल

एग्रीकल्चर मार्केट) को एक ऑनलाइन व्यापार मंच के रूप में लॉन्च किया। इस पोर्टल का संचालन स्मॉल फार्मर्स एग्रीबिज़नेस कंसोर्टियम (SFAC) द्वारा, एनईएफसीएल की एसआईकेएसएन डिवीजन प्रौद्योगिकी प्रदाता के सहयोग से किया जाता है। यह मंच किसानों, व्यापारियों और खरीदारों को वस्तुओं के ऑनलाइन लेन–देन की सुविधा देता है, बेहतर मूल्य खोजने में मदद करता है और किसानों की उपज के सुचारू विपणन की सुविधा प्रदान करता है।

ई–एनएएम भारत का सबसे बड़ा ई–ट्रेडिंग मंच है, जिसका लक्ष्य किसानों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष कृषि विपणन को प्रोत्साहित करना है। यह मंच ऑनलाइन व्यापार, गुणवत्ता आधारित मूल्य निर्धारण के लिए अस्सेइंग, निष्पक्ष ई–नीलामी, सटीक तौल और समय पर भुगतान जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है, जो इसे पारंपरिक प्रणाली से अधिक प्रभावी बनाती हैं। ई–एनएएम का मोबाइल ऐप किसानों और अन्य हितधारकों को कहीं भी और कभी भी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराता है। इस पोर्टल के माध्यम से एक ही स्थान पर आगमन, मूल्य, खरीद–बिक्री के प्रस्ताव और उनके उत्तर जैसी सेवाएँ मिलती हैं, जिससे लेन–देन की लागत घटती है, सूचना का अभाव कम होता है और देशभर के व्यापारियों की भागीदारी से वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण संभव होता है। इसके परिणामस्वरूप संस्थागत और भौतिक विकास, राज्यों में संतुलित प्रगति, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, किसानों की भागीदारी, बेहतर मूल्य, पारदर्शिता, बिचौलियों की कमी और नए बाजारों का विकास होता है।

भारत में ई–एनएएम की स्थिति

ई–एनएएम प्लेटफ़ॉर्म से 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 1522 मंडियाँ जुड़ी हुई हैं। इनमें उत्तर प्रदेश (213), मध्य प्रदेश (173), महाराष्ट्र (144), गुजरात (133) और राजस्थान (139) में सबसे अधिक मंडियाँ एकीकृत हैं। तमिलनाडु में 57, आंध्र प्रदेश में 5, तेलंगाना में 33, कर्नाटक में 6 और झारखंड में 19मंडियाँ सम्मिलित हैं। पूर्वोत्तर भारत में असम में 20, मणिपुर में 3 और त्रिपुरा में 19 मंडियाँ शामिल हैं, जबकि अंडमान–निकोबार और लक्षद्वीप में प्रत्येक में 1–1 मंडी पंजीकृत है। यह व्यापक नेटवर्क देशभर में कृषि विपणन को एकीकृत करने और डिजिटल रूप से मजबूत बनाने में सहायक है।

1. **ई–एनएएम के अंतर्गत व्यापार की जाने वाली वस्तुएं:** ई–एनएएम प्लेटफ़ॉर्म पर कई श्रेणियों में विविध कृषि उत्पादों का व्यापार होता है। इसमें खाद्यान्न/अनाज की 37, तिलहन की 14, फलों की 48, सब्ज़ियों की 59 और मसालों की 17 किस्में शामिल हैं। इसके अलावा, विविध (Misc) श्रेणी में 55 वस्तुएँ, औषधीय पौधों की 1, मेथी बीज की 1, चना की 2, गेहूं की 1, सिंघाड़े की 2 और स्वीट कॉर्न की 1 किस्म दर्ज है। यह व्यापक उत्पाद सूची दर्शाती है कि ई–एनएएम किसानों और खरीदारों को विभिन्न कृषि वस्तुओं के लेन–देन के लिए एक सुसंगठित और विस्तृत मंच उपलब्ध कराता है।
2. **ई–एनएएम प्रक्रिया प्रवाह:** ई–एनएएम की प्रक्रिया गेट एंट्री से आरंभ होती है, जहाँ किसान अपने उत्पाद का विवरण देकर इलेक्ट्रॉनिक गेट एंट्री स्लिप प्राप्त करता है। इसके बाद वह नीलामी मंच पर माल उतारता है और गुणवत्ता जांच (अस्सेइंग) के लिए नमूना प्रदान करता है। अस्सेइंग रिपोर्ट आने पर ई–बिडिंग शुरू होती है, जिसमें व्यापारी ऑनलाइन बोली लगाते हैं। नीलामी पूर्ण होने पर किसान को सर्वोच्च मूल्य की जानकारी दी जाती है, जिसे स्वीकृत करने पर तौल की प्रक्रिया होती है। तौल के बाद बिक्री रसीद जारी की जाती है, जिसमें लेन–देन से संबंधित सभी विवरण होते हैं। भुगतान नकद या बैंक ट्रांसफर से किया जाता है। अंत में, भुगतान होने पर मंडी अधिकारी गेट एग्जिट पास जारी करते हैं और उत्पाद व्यापारी को सौंप दिया जाता है।

साहित्य की समीक्षा

यादव और अन्य (2017) के अनुसार, एक प्रभावी विपणन प्रणाली के लिए सुशासन, नीतिगत सहयोग, बेहतर अवसंरचना और सेवाएँ, जैसे बाजार सूचना, अस्सेइंग और नेटवर्किंग आवश्यक हैं। इसलिए सुझाव दिया गया कि ई–एनएएम प्लेटफ़ॉर्म को इन सभी तत्वों को शामिल करके और सशक्त बनाया जा सकता है।

डे कुशांकुर (2016) के अध्ययन "नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटरू रोल–आउट रैशनल एंड रैमीफिकेशन्स" में राष्ट्रीय कृषि बाजार में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए विविध और विशेषज्ञ सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति का सुझाव दिया गया है। अध्ययन में बताया गया है कि लेन–देन में एक समझौता–आधारित प्रणाली और मूल्य व गुणवत्ता से संबंधित जानकारी जैसी सेवाएँ छोटे और सीमांत किसानों तक प्रभावी रूप से नहीं पहुँच पातीं। इसमें कृषि उत्पादों के गुणवत्ता मानकों और प्रत्येक बाजार में उचित अस्सेइंग के लिए आवश्यक अवसंरचना के बीच अधिक सामंजस्य की आवश्यकता बताई गई है, ताकि खरीदार उत्पाद की प्रामाणिकता सुनिश्चित कर सकें साथ ही, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की व्यवस्था से किसान इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे, जिससे इनपुट उपयोग दक्षता, मिट्टी की उर्वरता और फसल उत्पादकता में सुधार हो सकता है। एसएफएसी ने नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स को रणनीतिक भागीदार नियुक्त किया है, जो संबंधित एपीएमसी को अनुकूलित सेवाएँ प्रदान करने और उन्हें डिम्यूचुअलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट ट्रेडिंग पोर्टल से जोड़ने का कार्य भी देख सकता है।

डे कुशांकुर (2015) के अध्ययन में बताया गया कि पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के माध्यम से कृषि मूल्य श्रृंखला प्रबंधन को अपनाया जा सकता है। कृषि व्यवसाय मूल्य श्रृंखला में उत्पादन से लेकर क्रय, वितरण और उपभोग तक की सभी प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं, जो संसाधन प्रदाता/आपूर्तिकर्ता, परिवहनकर्ता, उत्पादक, प्रोसेसर, वितरक और बाजार जैसे विभिन्न घटकों को आपस में जोड़ती हैं।

अनुसंधान पद्धति

यह अध्ययन प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें डेटा उन किसानों से एकत्र किया गया जो एपीएमसी मंडी यार्ड में ई–एनएएम प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सक्रिय रूप से व्यापार कर रहे थे। झारखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए छह जिलों का चयन किया गया। प्रत्येक जिलों से एक–एक मंडी को अध्ययन में शामिल किया गया। निष्कर्ष चुनी गई मंडियों के किसानों से ई–एनएएम प्रक्रिया प्रवाह से संबंधित अवलोकन और जानकारी पर आधारित हैं। कुल 150 किसानों का चयन उद्देश्यपूर्ण नमूना विधि से किया गया, जिनमें प्रत्येक मंडी से 25 किसान शामिल गया है जबकि रांची, झारखंड मंडी से 28 किसानों को शामिल किया गया ताकि उनके विचारों का विश्लेषण किया जा सके। नमूना प्रक्रिया का विवरण तालिका में दिया गया है।

क्र.सं	एपीएमसी	किसान
01.	दुमका	25
02.	डालटनगंज	25
03.	सिमडेगा	25
04.	चाईबासा	25
05.	हजारीबाग	25
06.	पंडरा रांची	28
	कुल	153

अध्ययन से प्राप्त परिणाम

1. किसानों में ई–एनएएम प्रक्रिया और लाभों की जानकारी जानने के लिए किए गए सर्वे में पाया गया कि 57. 1 प्रतिशत किसान इससे परिचित हैं, जबकि 42.9 प्रतिशत अब भी अनजान हैं। यह स्थिति बताती है कि किसानों की समझ बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण और एक्सपोज़र विज़िट जैसे क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को मजबूत करना आवश्यक है।
2. किसानों से ई–नीलामी के लाभ जानने के लिए जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार, 153 उत्तरदाताओं में से 52. 86 प्रतिशत ने मूल्य के डिजिटल डिस्प्ले को प्रमुख लाभ माना, 20.38 प्रतिशत ने खरीदारों की अधिक

भागीदारी, 17.83 प्रतिशत ने बिचौलियों की कमी और 8.91 प्रतिशत ने अस्सेइंग आधारित मूल्य निर्धारण को लाभ बताया। यह दर्शाता है कि ई–एनएएम में ई–नीलामी प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी है।

3. ई–एनएएम में किसान को बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया है। यदि मूल्य कम लगे तो किसान पुनः नीलामी में भाग ले सकता है। सर्वे के अनुसार, 77.18 प्रतिशत किसान इस विकल्प के पक्ष में हैं, जबकि 22.82 प्रतिशत इसके विरोध में।

अध्ययन में पाया गया कि 57.1 प्रतिशत किसान ई–एनएएम की अवधारणा और लाभों से परिचित हैं। 84.6 प्रतिशत किसानों ने अस्सेइंग को आवश्यक माना, क्योंकि इससे मूल्य निर्धारण आसान होता है, गुणवत्ता की जानकारी मिलती है, व्यापार में विश्वास बढ़ता है और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होता है, जबकि 15.4 प्रतिशत इससे असहमत हैं। 87 प्रतिशत किसानों का मानना है कि मूल्य खोज के लिए अस्सेइंग जरूरी है, वहीं 13 प्रतिशत इसे अप्रभावी मानते हैं। 76 प्रतिशत किसानों ने ई–नीलामी को प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी बताया, जबकि 24 प्रतिशत ने विश्वास की कमी और प्रक्रिया की अदृश्यता पर असंतोष जताया। 90 प्रतिशत किसानों ने तौल को सटीक और पारदर्शी माना, लेकिन 10 प्रतिशत ने इसे पारंपरिक पद्धति जैसा बताया। 67 प्रतिशत किसान ई–पेमेंट प्रणाली से असंतुष्ट हैं और तत्काल नकद भुगतान को प्राथमिकता देते हैं। 53 प्रतिशत किसानों ने ई–एनएएम में पारंपरिक प्रणाली की तुलना में बेहतर मूल्य मिलने की बात कही। 61 प्रतिशत ने इसे अधिक खरीदारों तक पहुँचने का अवसर बताया। 77 प्रतिशत ने बोली स्वीकार या अस्वीकार करने के विकल्प को लाभकारी माना। 70 प्रतिशत किसानों का मानना है कि ई–एनएएम से उनकी वित्तीय प्रोफ़ाइल और बचत में सुधार हुआ है।

निष्कर्ष

ई–एनएएम पोर्टल वस्तुओं का आगमन, मूल्य, खरीद–बिक्री प्रस्ताव और उनके उत्तर जैसी सुविधाएँ एक ही मंच पर देता है, जिससे लेन–देन की लागत घटती है, सूचना असमानता कम होती है और वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण को बढ़ावा मिलता है। इसका सकारात्मक प्रभाव राज्यों में संतुलित विकास, प्रतिस्पर्धा, किसानों की भागीदारी, पारदर्शिता, बिचौलियों की कमी और नए बाजारों के निर्माण में दिखता है। किसानों ने इसे मूल्य खोज और विश्वास बढ़ाने में सहायक माना है, जबकि चुनौतियों में ऑनलाइन प्रणाली की जानकारी, अस्सेइंग मशीनरी, अवसंरचना और ई–भुगतान शामिल हैं। इनसे निपटने के लिए प्रचार, कानूनी सुधार, प्रशिक्षण, अवसंरचना विकास और प्रोत्साहन आवश्यक हैं।

सुझाव

ई–एनएएम को सभी मंडियों में विस्तार करने का सुझाव दिया गया है, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़े और किसानों को अधिक लाभ प्राप्त हो। किसानों में ई–एनएएम की प्रक्रिया, फायदे और आर्थिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से अभियान चलाना आवश्यक है। अस्सेइंग को मजबूत करने हेतु प्रमाणित उपकरण और वस्तु–विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएँ, साथ ही अधिक भीड़ के समय पीपीपी मॉडल पर तृतीय पक्ष अस्सेइंग प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएँ। तौल मशीनों को ई–एनएएम प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ा जाए और एफपीओ को विशेष रियायतें व प्रोत्साहन देकर इसमें शामिल किया जाए। कुछ मंडियों को मॉडल ई–एनएएम मंडी के रूप में विकसित कर प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाए तथा प्रदर्शन और अवसंरचना के आधार पर मंडियों का मूल्यांकन व वर्गीकरण कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाए। मंडियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पीपीपी मॉडल अपनाया जाए और एफपीओ को व्यापारी तथा कमीशन एजेंट के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाए।

संदर्भ सूची

1. डे, कुशांकुर (2016) राष्ट्रीय कृषि बाजाररू तर्क, क्रियान्वयन और प्रभाव, *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली,* 51(19), 224–230।

2. राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एनआईएएम) (2016) किसानों को इलेक्ट्रॉनिक बाजार (ई–एनएएम) से जोड़ना, http://ccsniam.gov.in/images/pdfs/E-NAM-Status-&-Way-Forward.pdf, Accessed on 08/07/2025.

3. चंद, रमेश (2016) राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई–प्लेटफ़ॉर्म, *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली,* LI(28), 82–87।

4. चंद, रमेश (2017) किसानों की आय दोगुनी करनाः तर्क, रणनीति, संभावनाएँ और कार्य योजना, नीति आयोग नीति पत्र संख्या 1/2017, नीति आयोग, भारत सरकार।

5. कुमार, वी.; चौहान, एन.एस. और बीबी एच. (2018) कृषि उपज बाजार समिति के प्रति किसानों का रवैया, *गुजरात. जे. एक्सटेंशन,* एडु, 29, 224–226।

6. सिंह, सुखपाल एवं भोघल, श्रुति (2015) पंजाब की समकालीन कृषि अर्थव्यवस्था में कमीशन एजेंट प्रणाली का महत्व, *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली,* L(45), 71–78।

7. सिंह, सुखपाल (2012) पंजाब कृषि के संस्थागत और नीतिगत पहलूः लघु जोतधारक दृष्टिकोण, *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली,* 47(4), 46–52।

8. थंकाचन एस. और किरुबाकरन एस. (2014) भारतीय किसानों के साथ ई–कृषि पर एक सर्वेक्षण किया गया, *कंप्यूटर विज्ञान और मोबाइल कंप्यूटिंग के अंतर्राष्ट्रीय जे,* 3(2), 8–14।

9. नंदी, रवि; वोल्फगैंग, बोकेलमन्ना; विश्वनाथ, गौडरू नित्या; गुस्तावो, डायस (2015) भारत में जैविक फलों और सब्जियों के उत्पादन के प्रति छोटे धारक जैविक किसानों का दृष्टिकोण, उद्देश्य और बाधाएं, *एमिरेट्स जर्नल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर,* 27(5), 396– 406।

10. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (तिथि निर्दिष्ट नहीं) किसानों की आय दोगुनी करने पर समिति की रिपोर्ट (खंड 4, 9, 11)। प्राप्त किया गया, http://www.agricoop.nic.in/doubling-farmers, Accessed on 13/08/2025

****